भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 456
मंगलवार, 4 फ़रवरी, 2025/15 माघ, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

प्राथमिक कृषि ऋण समितियां

456 श्री दुष्यंत सिंहः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल), भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) और नेशनल कोऑपरेटिव आर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) का ब्यौरा क्या है और देश भर में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए इन संगठनों द्वारा क्या पहल की गई है;
(ख) क्या केन्द्र सरकार का उद्देश्य पंचायतों में व्यवहार्य सहकारी समितियों की स्थापना करना है और विशेष रूप से डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए और उनके गठन और विकास को सहायता प्रदान करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) सॉफ्टवेयर से जोड़कर डिजिटाइज करने के लिए कदम उठाए हैं और इन उपायों का उद्देश्य पीएसीएस के भीतर दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) आज की तारीख तक ईआरपी सॉफ्टवेयर में शामिल पीएसीएस की कुल संख्या कितनी है और उन क्षेत्रों या राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां पीएसीएस का कार्यान्वयन सबसे सफल रहा है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क): केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन से सहकारिता मंत्रालय ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन राष्ट्रीय स्तर की तीन नई सहकारी समितियों की स्थापना की है:

i. राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL),
ii. राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL),
iii. भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) ।

उपर्युक्त प्रत्येक समिति के लिए निर्दिष्ट कार्यकलापों में रुचि रखने वाली सभी स्तरों की सहकारी समितियां इनके सदस्य बनने के लिए पात्र हैं । तत्संबंधी ब्योरा निम्नानुसार हैं:

1. राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL): सहकारी समितियों और संबंधित संस्थाओं के अधिशेष माल और सेवाओं का निर्यात कार्य के साथ-साथ संवर्धनात्मक कार्यकलाप करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको), कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड), गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (GCMMF) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा प्रवर्तित किया गया है । अब तक 5,438 सहकारी समितियां राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) की सदस्य बन गई हैं ।

देश भर में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए NCEL द्वारा की गई पहलें:

i. NCEL ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 4,121 करोड़ रुपये मूल्य के 36 कृषि उत्पादों का 10,42,297.81 मीट्रिक टन का निर्यात किया ।
ii. NCEL ने 26.40 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है और वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सदस्य सहकारी समितियों को चूकता शेयर पूंजी पर 20% की दर से लाभांश का वितरण किया है ।
iii. NCEL ने कृषि और संबंध क्षेत्र के ऐसी उत्पादों, जिनका विश्व स्तर पर तुलनात्मक लाभ है और जिन्हें NCEL के माध्यम से निर्यात के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, की पहचान करने और एक उपयुक्त ऐजेंसी नामित करने, जो NCEL के साथ राज्य सरकार की ओर से नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से अनुरोध किया है ।

2. राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL): PACS/FPOs सहित अपने सदस्य सहकारी समितियों के माध्यम से जैविक उत्पादों का एकत्रण, प्रमाणन, परीक्षण, प्रापण, भंडारण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक सुविधाओं, विपणन के लिए संस्थागत् सहयोग प्रदान करने हेतु NCOL को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB), गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (GCMMF), भारतीय राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ मर्यादित (NAFED), भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (NCCF) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा प्रवर्तित किया जा रहा है । NCOL विभिन्न स्तरों पर सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित जैविक पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रामाणिक और प्रमाणित जैविक उत्पादों के विपणन में मदद करेगा । अब तक 5,184 सहकारी समितियां NCOL की सदस्य बन गई हैं ।

देश भर में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए NCOL द्वारा की गई पहलें:

i. NCOL ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सफल आउटलेट के माध्यम से जैविक उत्पादों के लिए 'भारत ब्रांड' का शुभारंभ किया है और सफल के दुकानों और बाजार के अन्य चैनलों में आटा, दलहन, स्वीटनरों और मसाले सहित 20 जैविक उत्पादों का विक्रय शूरू कर दिया है ।
ii. NCOL ने उत्तराखंड ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड (UOCB) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और उत्तराखंड से 40 मीट्रिक टन प्रीमियम जैविक बासमती धान की खरीद की है । किसानों को बाजार मूल्य से ₹5 प्रति किलोग्राम अधिक प्रीमियम प्राप्त हुआ ।
iii. चालू रबी मौसम के दौरान NCOL ने सेवा प्रदाताओं के लिए सेवा शुल्क सहित ₹5 प्रति किलोग्राम अतिरिक्त प्रीमियम प्रस्तावित कर विदर्भ, महाराष्ट्र से जैविक-प्रमाणित तुअर (पिजन पी) की खरीद शुरू की है ।

iv. NCOL ने प्रमाणित जैविक उत्पादों की खरीद के लिए 8 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नोडल अधिकारियों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है और 24 अन्य राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने के लिए नोडल अधिकारियों की पहचान की है ।

v. NCOL ने राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) के अधीन सहकारी समितियों को कानूनी संस्था के रूप में शामिल करने के लिए APEDA के साथ सहभागिता की है ।

3. भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL): BBSSL को फसल पैदावर में सुधार हेतु सहकारी नेटवर्क के माध्यम से एकल ब्रांड नाम के अंतर्गत उन्नत बीजों का उत्पादन, प्रापण और वितरण और देशज पारंपरिक बीजों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक प्रणाली विकसित करने के लिए इफको, कृभको, नेफेड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और एनसीडीसी द्वारा प्रवर्तित किया जा गया है । BBSSL सहकारी समितियों के माध्यम से भारत में उन्नत बीजों के उत्पादन में वृद्धि कर आयातित बीजों पर निर्भरता को घटाएगा, कृषि उत्पादन में वृद्धि करेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगा । अब तक 17,425 सहकारी समितियां BBSSL के सदस्य बन गई हैं ।

देश भर में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए BBSSL द्वारा की गई पहलें:

i. BBSSL निजी सहित सभी उपलब्ध बाजार चैनलों के माध्यम से 'भारत बीज' के वितरण के लिए रिटेल आउटलेटों की स्थापना कर रहा है ।

ii. रबी 2023-24 मौसम के दौरान 11,575.45 क्विंटल बुनियादी बीजों का उत्पादन किया गया है।

iii. खरीफ 2024 मौसम के दौरान 3,820 क्विंटल बुनियादी बीजों का उत्पादन किया गया है।

iv. रबी 2024 मौसम के दौरान BBSSL ने लगभग 1,64,804 क्विंटल बुनियादी और प्रामाणिक बीजों के उत्पादन के लिए 6 राज्यों में 5,596 हेक्टेयर भूमि में 8 फसलों के 49 किस्मों की बुआई की है ।

v. BBSSL को अब तक 11 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में लाइसेंस प्राप्त हुआ है ।

(ख): सरकार ने दिनांक 15.02.2023 को देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त करने और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच सघन करने की योजना अनुमोदित की है । इस योजना में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB), राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) और राज्य सरकारों के सहयोग से डेयरी अवसंरचना विकास कोष राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, आदि सहित भारत सरकार की मौजूदा विभिन्न योजनाओं के अभिसरण द्वारा आगामी पांच वर्षों में भारत के अल्पसेवित क्षेत्रों सहित सभी पंचायतों/गांवों को आच्छादित करने के लिए नए बहुउद्देशी पैक्स, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों स्थापित किए जाएंगे ।

इस योजना का प्रभावशाली और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने NABARD, NDDB और NFDB के समन्वय से दिनांक 19.09.2024 को एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (मार्गदर्शिका) का विमोचन किया है जिसमें सभी संबंधित हितधारकों के लिए लक्ष्यों और समयसीमा का उल्लेख है । मार्गदर्शिक के अनुसार, जमीनी स्तर पर इस योजना का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा जिला स्तर पर संयुक्त कार्य समिति (JWC) का गठन किया गया है ।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार इस पहल की शुभारंभ से लेकर अब तक, देश में 3,654 नए बहुउद्देशीय PACS, 8256 डेयरी और 990 मात्स्यिकी सहकारी समितियां पंजीकृत की गई हैं ।

(ग)**:** भारत सरकार द्वारा ₹2,516 करोड़ की कुल वित्तीय परिव्यय से कार्यशील पैक्स के कंप्यूटरीकरण की परियोजना कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें सभी कार्यशील पैक्स को एक ERP (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाकर राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड के साथ लिंक करना है । इस कॉमन ERP सॉफ्टवेयर को देश भर में परियोजना के सभी पैक्स को उनके सभी कार्यों, क्रेडिट और गैर-क्रेडिट, के डाटा का संकलन करने के लिए दिया जा रहा है । यह सॉफ्टवेयर राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलनशील है ।
ERP (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर एक कॉमन एकाउंटिंग सिस्टम (CAS) और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन (MIS) के माध्यम से पैक्स के प्रदर्शन में कुशलता लाएगा । इसके अलावा, पैक्स के शासन और पारदर्शिता में सुधार आएगा जिससे ऋणों का त्वरित संवितरण, लेनदेन लागतों में कमी, भुगतान असंतुलनों में कमी, राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) निर्बाध लेखांकन सुनिश्चित होगा ।

(घ)**:** ईआरपी सॉफ्टवेयर पर कुल 50,455 पैक्स को शामिल किया गया है और 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा हार्डवेयर की खरीद की गई है। ऑनबोर्ड PACS की राज्य-वार सूची **अनुलग्नक** के रूप में संलग्न है ।

अनुलग्नक

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	कंप्यूटरीकरण के लिए चयनित PACS	ऑनबोर्ड किए गए ERP
1.	महाराष्ट्र	12,000	10,979
2.	राजस्थान	6,781	4,206
3.	गुजरात	5,754	5,249
4.	उत्तर प्रदेश	5,686	2,978
5.	कर्नाटक	5,491	2,077
6.	मध्य प्रदेश	4,536	4,516
7.	तमिलनाडु	4,532	4,529
8.	बिहार	4,495	4,440
9.	पश्चिम बंगाल	4,167	1,103
10.	पंजाब	3,482	1,720
11.	आंध्र प्रदेश	2,037	1,734
12.	छत्तीसगढ़	2,028	2,010
13.	हिमाचल प्रदेश	1,789	836
14.	झारखंड	1,500	1,467
15.	हरियाणा	710	617
16.	उत्तराखंड	670	185
17.	असम	583	580
18.	जम्मू और कश्मीर	537	531
19.	त्रिपुरा	268	245
20.	मणिपुर	232	45
21.	नागालैंड	231	33
22.	मेघालय	112	103
23.	सिक्किम	107	107
24.	गोवा	58	35
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समुह	46	46
26.	पुड्डुचेरी	45	37
27.	मिजोरम	25	25
28.	अरुणाचल प्रदेश	14	11
29.	लद्दाख	10	9
30.	दादर और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप	4	2
कुल		67,930	50,455